ई- बसों के लिए हर 25 किमी पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे

एक्सपो

- तीन दिवसीय 'उत्तर प्रदेश ऊर्जा एक्सपो 2025' का समापन
- सोलर ऊर्जा का उपभोग घरेलू आवश्यकताओं के लिए ही अधिकाधिक करें

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बैटरी स्टोरेज सिस्टम में सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रही है। हम निवेशकों को राज्य में बैटरी स्टोरेज प्लांट स्थापित करने का आह्वान करते हैं, और उन्हें पूर्ण सरकारी समर्थन का आश्वासन देते हैं। राज्य में बिजली सप्लाई की कोई कमी नहीं है और आईआईटी कानपुर और बीएचयू की मदद से हम सौर ईपीसी के लिए मजबूत फीडर्स और बुनियादी ढांचा विकसित कर रहे हैं। यह बात यूपीपीसीएल के मुख्य अभियंता दीपक रायजादा ने कही। वह शनिवार को गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तीन दिवसीय 'उत्तर प्रदेश ऊर्जा एक्सपो 2025' के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। वहीं यूपीएसआरटीसी के सर्विस मैनेजर रमेश कुमार ने कहा कि सरकार पहले ही इलेक्ट्रिक बसों के लिए परमिट और रोड टैक्स में छूट प्रदान कर चुकी है। पीपीपी मॉडल के तहत हर 25 किमी पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना राज्य में इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले ही भारत के कुल ईवी उपयोग में 15 प्रतिशत योगदान दे चुका है और राज्य 2030 तक इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े का चरणबद्ध रूप से रोल आउट पूरा करने की योजना बना रहा है। राजमार्गों पर पीपीपी मॉडल के तहत ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की योजना बनाई गई है, जिनमें से कई यूपीएसआरटीसी द्वारा संचालित किए जाएंगे। मध्यांचल विद्युत निगम के निदेशक (वाणिज्य) योगेश कुमार ने बताया कि सरकार बिजली भंडारण के लिए उपकेंद्रों का निर्माण करने की योजना बना रही है। बीपीसीएल हेड रिन्यूएबल एनर्जी रंजन नायर ने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन की अधिक लागत, महंगा भंडारण, ऊर्जा का सुरक्षित रखरखाव और संयंत्रों के लिए विदेश आयातों पर निर्भरता चुनौती बनी हुई है।

पीएचडीसीसीआई की ओर से शनिवार को आईजीपी में आयोजित एनर्जी एक्सपो के समापन समारोह में शामिल उद्यमी व अधिकारी।